

[2023] 4 एस. सी. आर. 188

सबरमति गैस लिमिटेड

बी.

शाह एलॉयस लिमिटेड

(2020 की सिविल अपील संख्या 1669)

04 जनवरी, 2023

[अजय रस्तोगी और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss. 6 , 8 , 9 , 62 , 238 ए, 252-बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 -

प्रत्यर्थी ने चालान के भुगतान में चूक की-प्रत्यर्थी ने बी. आई. एफ. आर. से संपर्क किया और इसे 'बीमार इकाई' घोषित कर दिया-अपीलकर्ता ने बकाया बकाया की वसूली के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए बी. आई. एफ. आर. से अनुमति मांगी-इसके तुरंत बाद, एस. आई. सी. ए. को आई. बी. सी. के लागू होने से निरस्त कर दिया गया-बी. आई. एफ. आर. के कार्यात्मक अधिकारी बनने पर, अपीलकर्ता ने यू / आई. बी. सी. की धारा 8-प्रत्यर्थी ने भुगतान करने के दायित्व को अस्वीकार कर दिया माँगी गई राशि-अपीलार्थी ने यू/एस आवेदन दायर किया। 9 एन. सी. एल. टी. के समक्ष आई. बी. सी. ने प्रत्यर्थी के परिचालन लेनदार के रूप में अपनी क्षमता में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत करने की मांग की-उक्त आवेदन को एन. सी. एल. टी. द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच पहले से मौजूद विवाद की सीमा और अस्तित्व से बाधित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था-एन. सी. एल. टी. के फैसले के खिलाफ अपील को भी एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया था-उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दे: चाहे वह यू/एस द्वारा दायर किए गए आवेदन के संबंध में सीमा की अवधि की गणना में हो। 9 , आई. बी. सी. वह अवधि जिसके दौरान परिचालन लेनदार का अधिकार है

निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही करें या मुकदमा करें जो एस के आधार पर निलंबित रहता है। 22 (1) बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान अधिनियम, 1985) (एस. आई. सी. ए.) को बाहर रखा जा सकता है, जैसा कि यू/एस. 22 (5) एस. आई. सी. ए. और क्या प्रत्यर्थी ने एक विवाद उठाया है जिसे अपने और अपीलार्थी के बीच 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो आवेदन यू/एस को खारिज करने की गारंटी देता है। 9 सीमा पर आई. बी. सी.-आयोजित: जब सी. आई. आर. पी. यू/एस. शुरू करने के लिए सीमा अवधि। 9 , आई. बी. सी. की गणना डिफ़ॉल्ट की तारीख से की जानी है, इसके विपरीत

188 सबरमति गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड

आई. बी. सी. के प्रारंभ होने की तिथि और उसके लिए निर्धारित अवधि, एस. द्वारा प्रदान की गई तीन वर्ष है। 137 सीमा अधिनियम, 1963 और यह डिफॉल्ट की तारीख से शुरू होगा और केवल एस के आवेदन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 5 सीमा अधिनियम, 1963 का यह दायित्व है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण देरी को माफ करने के दावे पर विचार करे-अवधि के अपवर्जन के प्रावधानों के अभाव में

आवेदन यू/एस के संबंध में। 9 , आई. बी. सी., एस. के संयुक्त पठन के बावजूद। 238 ए, आईबीसी और सीमा अधिनियम के तहत प्रावधान क्या है

इस तरह के एक पक्ष के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध देरी यू/एस को माफ करने के लिए एक पर्याप्त कारण के रूप में निर्दिष्ट करना है। 5 जहां तक 'पूर्व-विद्यमान विवाद' का संबंध है, अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे के संबंध में प्रतिवादी के विवाद की प्रकृति पर विचार करते हुए, न्यायाधिकरणों के समवर्ती निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि मांग की प्राप्ति से पहले पक्षों के बीच 'पूर्व-विद्यमान विवाद' मौजूद था।

यू/एस पर ध्यान दें। 8 , आई. बी. सी.-आवेदन यू/एस की बर्खास्तगी। 9 , पूर्व-विद्यमान विवाद के आधार पर आई. बी. सी. को स्पष्ट रूप से अवैध या विकृत नहीं माना जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1. धारा 7 के संबंध में, आई. बी. सी. धारा 9, आई. बी. सी. पर लागू होगी। संक्षेप में, जैसा कि धारा 9, आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन से संबंधित है, आई. बी. सी. के लागू होने की तारीख, अर्थात्,

01.12.2016 धारा 9, आई. बी. सी. के तहत सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन के लिए सीमा का ट्रिगर बिंदु और सीमा की अवधि उस तारीख से तीन साल होगी जब सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान किए गए अनुसार आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है। और आगे यह कि आई. बी. सी. के तहत आवेदन करने का अधिकार उस तारीख को प्राप्त होगा जब डिफॉल्ट होता है और यह केवल इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है

सीमा अधिनियम की धारा 5 का अनुप्रयोग। [पैरा 23] [209-ई-एफ] 2. जब धारा 9 के तहत सी. आई. आर. पी. शुरू करने की सीमा अवधि, आई. बी. सी. की गणना आई. बी. सी. शुरू होने की तारीख और उसके लिए निर्धारित अवधि के विपरीत, चूक की तारीख से की जानी है, तो आई. बी. सी. की धारा 137 द्वारा प्रदान की गई तीन साल की अवधि है।

चूक की तारीख और केवल सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के आवेदन द्वारा बढ़ाई जा सकती है, यह निर्णय लेने पर बाध्य है [2023] 4 एस. सी. आर. होने पर देरी को माफ करने के दावे पर विचार करने का अधिकार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक बार जब संबंधित कार्यवाही सीमा की अवधि से परे दायर की जाती है। जैसा कि सीमा अधिनियम की धारा 5 से संबंधित है, 'पर्याप्त कारण' दिखाना देरी को माफ करने का एकमात्र मानदंड है। पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए एक कानूनी रोक है।

एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) के आधार पर एक औद्योगिक कंपनी और स्पष्ट रूप से, जब कोई पक्ष इस प्रकार बी. आई. एफ. आर. की अनुमति के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने से कानूनी रूप से अक्षम था और यहां तक कि आवेदन की अनुमति पर भी कानूनी कार्यवाही में बहिष्कृत के निलंबन की अवधि नहीं दी गई थी, तो इसके लिए सीमा की अवधि की गणना करना है।

एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (5) के संदर्भ में ऐसे अधिकार का प्रवर्तन। ऐसी अवधि के अपवर्जन के प्रावधानों के अभाव में - धारा 9, आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन, धारा 238 ए, आई. बी. सी. और सीमा के तहत प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन के बावजूद

ऐसे पक्ष के लिए कानूनी रूप से जो अधिनियम उपलब्ध है, वह सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए एक पर्याप्त कारण के रूप में निर्दिष्ट करना है। ऐसी स्थिति में, किसी विशेष मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार, देरी की अवधि और धारा 22 (1), एस. आई. सी. ए. आदि के तहत अधिकार के निलंबन द्वारा कवर की गई अवधि, देरी की माफी के सवाल पर विचार किया जाना चाहिए ताकि इसके परिणामस्वरूप अन्याय न हो क्योंकि पक्षकार सांविधिक रूप से था। संबंधित औद्योगिक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से रोका गया। [पारस 24,25] [209-एच; 210-ए-एफ]

3. 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के अस्तित्व में धारा 9 आई. बी. सी. के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए

सीमा। इसलिए, सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्थी ने 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के रूप में वर्णित विवाद उठाया था ताकि धारा 9, आई. बी. सी. के तहत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करना। प्रासंगिक स्थिति में केवल मोबिलॉक्स इनोवेशन (पी) लिमिटेड के अवलोकन को याद दिलाना उचित है कि भूसे से अनाज को अलग करने का कार्य करते समय न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव पक्ष के सफल होने की संभावना है। यह काफी है।

यह कि पक्षकारों के बीच कोई विवाद मौजूद है और दूसरे शब्दों में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद था जिसके लिए न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से जाँच की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थी के विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि संदर्भित SABARMATI GASS LIMITED v.

शाह एलॉयस लिमिटेड

अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे के संबंध में इससे पहले समवर्ती निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं है - न्यायाधिकरण कि धारा 8,2 के तहत मांग सूचना की प्राप्ति से पहले पक्षों के बीच एक 'पूर्व-मौजूदा विवाद' मौजूद था

दूसरे शब्दों में, 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के आधार पर धारा आई. बी. सी. के तहत आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है।

स्पष्ट रूप से अवैध या विकृत। [पैरा 32,38] [212-ए-बी; 217-ई

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड बनाम कीरूसा सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड

(2018) 1 एससीसी 353; बी. के. शैक्षिक सेवाएँ निजी

सीमित बी। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी

633 [2018] 12 एस. सी. आर. 794; बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और

एन. आर. (2020) 15 एस. सी. सी. 1; मैक्केरी बैंक लिमिटेड बनाम। शिल्पी

केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एससीसी 674: [2017]

13 एससीआर 751-पर निर्भर।

परमजीत सिंह पाथेजा बनाम। आईसीडीएस लिमिटेड (2006) 13 एससीसी

322 [2006] 8 पूरक। एससीआर 178; कैलाश नाथ अग्रवाल और ओआरएस। बी. प्रदेश औद्योगिक और निवेश

निगम यू. पी. लिमिटेड और ए. एन. आर. (2003) 4 एससीसी 305: [2003] 1 एससीआर 1159; केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। एम/एस।

अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड (2015) 1 एस. सी. सी. 166: [2014] 14

एस. सी. आर. 1097; इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक

और एन. आर. (2018) 1 एससीसी 407 [2017] 8 एससीआर 33 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 8 पूरक। एससीआर 178

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2003] 1 एससीआर 1159

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[2014] 14 एससीआर 1097

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2018] 12 एससीआर 794

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

(2020) 15 एससीसी

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2017] 13 एससीआर 751

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

31 [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1669

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पीयूष जोशी, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सुमिती यादव, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सजल जैन, सुश्री पेम्पा राज, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री गौरी रसगोत्रा, सुमित अत्री, सुश्री रितु आनंद विश्वकर्मा, सत्य आनंद, सुश्री एना कपूर, मैसर्स।

सिरिल अमरचंद मंगलदास, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी. टी. रविकुमार जे.

1. दिवाला और दिवालियापन की धारा 62 के तहत यह अपील

27.06.2019 सी. पी. (आई. बी.) संख्या 516/9/एन. सी. एल. टी./ए. एच. एम./2018 कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद बेंच, (एन. सी. एल. टी.) ने आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत दायर आवेदन को 'शाह अलॉयज लिमिटेड' (इसके बाद के रूप में संदर्भित) के परिचालन लेनदार के रूप में खारिज कर दिया।

' उत्तरदाता ')।

2. मुख्य रूप से शीर्षक वाली अपील में, कानून के दोहरे प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है:

चाहे सीमा की अवधि की गणना में

(i)

धारा 9, आई. बी. सी. के तहत दायर एक आवेदन के संबंध में

अवधि जिसके दौरान परिचालन लेनदार का कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ आगे बढ़ने या मुकदमा करने का अधिकार है जो बीमार की धारा 22 (1) के आधार पर निलंबित रहता है।

औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान अधिनियम, 1985) (एस. आई. सी. ए.) को धारा 22 के तहत बाहर रखा जा सकता है।

(5) एस. आई. सी. ए. का?

सबरमति गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

क्या प्रत्यर्थी ने कोई विवाद उठाया है जो है

((ख)

अपने और अपीलार्थी के बीच 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के रूप में वर्णित जो सीमा पर आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन को खारिज करने की गारंटी देता है?

कथित जुड़वां प्रश्नों पर विचार करते समय प्रासंगिकता के कुछ अन्य संबद्ध प्रश्न भी विचार के लिए सामने आ सकते हैं, जिन्हें हम उचित समय पर बताएगा और विचार करेगा। प्रतिवादी-निगम

ऋणी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के समक्ष 2010 के मामले संख्या 13 में याचिकाकर्ता था और इसमें अपीलार्थी 2010 के मामले संख्या 13 में 2013 के विविध आवेदन संख्या 432 में आवेदक था।

3. अपीलार्थी श्री श्याम के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना

दीवान और श्री एस. गुरु कृष्ण कुमार, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील।

4. ऊपर उल्लिखित और इसके बाद उल्लिखित किए जाने वाले प्रश्नों पर निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में विचार करने की आवश्यकता है:

प्रत्यर्थी को अपनी विनिर्माण आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक गैस की वाणिज्यिक आपूर्ति की आवश्यकता थी। 30.05.2008 पर इसे सुविधाजनक बनाने के लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने एक गैस बिक्री समझौता (जी. एस. ए.) किया जिसके तहत और जिसके तहत अपीलार्थी को जी. एस. ए. के साथ संलग्न अनुलग्नक-2 में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने का दायित्व था और यह अनुबंध का भी हिस्सा है। जी. एस. ए. के खंड 11.2 के अनुसार, चालान की गई किसी भी राशि के संबंध में किसी भी विवाद के बावजूद, प्रत्यर्थी जी. एस. ए. के अनुसार भुगतान को रोक नहीं सका। अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी ने चालान का भुगतान करने में चूक की क्योंकि उसने नवंबर, 2011 से केवल आंशिक अनियमित भुगतान किए। इस बीच, प्रतिवादी ने बी. आई. एफ. आर. से इसे 'बीमार इकाई' घोषित करने और एस. आई. सी. ए. के तहत प्रावधानों के संदर्भ में इसके पुनर्वास के लिए एक योजना की सिफारिश के लिए संपर्क किया। संदर्भ को बी. आई. एफ. आर. द्वारा 2010 के मामले संख्या 13 के रूप में स्वीकार किया गया था और 31.08.2010 दिनांकित आदेश के अनुसार प्रतिवादी को 'बीमार कंपनी' घोषित किया गया था। यह अपीलार्थी का मामला है कि एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के आधार पर प्रत्यर्थी पर रोक थी और इसलिए, वह बी. आई. एफ. आर. की अनुमति प्राप्त किए बिना, बकाया देय राशि के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकता था। आई. डी. 1 पर अपीलार्थी ने गैस की आपूर्ति रोक दी और फिर बी. आई. एफ. आर. के समक्ष लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप किया, 13 2010 से 08.03.2013 पर, विविध आवेदन संख्या के अनुसार।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

432 2013 में अपीलार्थी ने बी. आई. एफ. आर. से प्रत्यर्थी के खिलाफ 2 करोड़ रुपये के बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी। 4,71,56,095 / - . 09.09.2015 पर, बी. आई. एफ. आर. ने उस पर एक आदेश पारित किया। इसके तुरंत बाद, सटीक रूप से, डब्ल्यू. ई. एफ. 01.12.2016, एस. आई. सी. ए. को निरस्त कर दिया गया।

5. अपीलार्थी के अनुसार, बी. आई. एफ. आर. कार्यात्मक अधिकारी बन गया और प्रतिवादी के मामले सहित उसके समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया गया और धारा 8 और 9 सहित आई. बी. सी. की कई धाराएं आई. डी. 1 पर लागू हो गईं। इसलिए, आई. बी. सी. के अधिनियमन के बाद, अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 8 के तहत दिवाला और दिवालियापन (आई. बी. सी. के लिए आवेदन) के नियम 5 के साथ पढ़ने के लिए 01.04.2017 पर मांग नोटिस जारी किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण), नियम 2016, प्रपत्र संख्या 3 में रुपये के परिचालन ऋण के भुगतान की मांग करते हैं। 4,71,56, 094.76 / - . 10.04.2017 पर, प्रत्यर्थी ने उपरोक्त मांग नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी आई है और कनेक्शन कटने के कारण भी भारी नुकसान हुआ है।

प्रत्यर्थी का परिचालन लेनदार। उक्त आवेदन को एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांक 27.06.2019 के आदेश के अनुसार इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच 'पूर्व-विद्यमान विवाद' की सीमा और अस्तित्व द्वारा वर्जित। यह एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष उसी को चुनौती देने वाली अपील है जो अंततः विवादित फैसले में समाप्त हुई।

6. हम सबसे पहले सीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर धारा 9, आई. बी. सी. के तहत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करने के कारण उत्पन्न होने वाले कानून के पहले प्रश्न पर विचार करेंगे। उपरोक्त के आलोक में

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और दलीलों पर अपीलकर्ता का तर्क होगा कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. एस. आई. सी. ए. की धारा 22 की उप-धारा (1) और (5) के संचयी प्रभाव पर गौर करने और उसकी सराहना करने में विफल रहे हैं, जबकि धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। तर्क के विस्तार में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. यह समझने में विफल रहे कि प्रतिवादी को बी. आई. एफ. आर. द्वारा अपने दिनांक 31.08.2010 के आदेश के अनुसार एक 'बीमार कंपनी' के रूप में भर्ती किया गया था और इसलिए, धारा 22, एस. आई. सी. ए. की उप धारा (5) के आधार पर एस. आई. सी. ए. के तहत निलंबन की अवधि अर्थात्, 31.08.2010 से 01.12.2016 तक, सीमा की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना चाहिए था। अपीलार्थी के अनुसार, चूंकि धारा 9 के तहत आवेदन, आई. बी. सी. 20.08.2018 पर दायर किया गया था, इस तरह के बहिष्कार का लाभ देते हुए, निश्चित रूप से, आवेदन को अच्छी तरह से सबरमति गैस लिमिटेड v.

शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रदान की गई 3 साल की सीमा अवधि के भीतर। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने परमजीत सिंह पाथेजा बनाम में निर्णय पर भरोसा रखा। आई. सी. डी. एस. लिमिटेड', विशेष रूप से पैराग्राफ 43 (vii), इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि अपीलार्थी पर कानून द्वारा निहित अधिकार की प्राप्ति के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही को रखने या जारी रखने के लिए एक वैधानिक प्रतिबंध था।

7. अपीलार्थी की दलीलों का विरोध करते हुए और विवादित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रतिवादी का तर्क होगा कि एन. सी. एल. टी. और

धारा 9 आवेदन में अपीलार्थी के रुख और आई. बी. सी. की धारा 8 के तहत मांग सूचना के बीच, जो कथित बकाया राशि से संबंधित है। यह भी तर्क दिया जाता है कि कार्रवाई के कारण की तारीख के संबंध में भी ऐसी विसंगति मौजूद है क्योंकि धारा 9 के आवेदन के अनुसार कथित ऋण नवंबर, 2011 को और उससे देय था और मांग सूचना के अनुसार तथाकथित ऋण 9 जुलाई, 2012 को और उससे देय था और दोनों ही मामलों में, धारा 9 के आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि यह केवल वर्ष 2018 में दायर किया गया था। कहने के लिए, कथित चूक से 3 साल से अधिक। एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (5) के तहत अवधि के अपवर्जन का लाभ अपीलार्थी को धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदन के संबंध में सीमा की अवधि की गणना करने के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रत्यर्थी के अनुसार, धारा 22 (1), एस. आई. सी. ए. ने कार्रवाई के कारण को चलाने के खिलाफ एक व्यापक संरक्षण प्रदान नहीं किया है और इसका उद्देश्य जबरदस्ती प्रकृति की कानूनी कार्यवाही को निलंबित करना है ताकि किसी उद्यम की संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि वसूली के लिए आवेदन दायर करना अनुमत था और धारा 22 (1), एस. आई. सी. ए. इसे निषिद्ध नहीं किया गया था और इसने संबंधित औद्योगिक कंपनी की संपत्तियों के खिलाफ केवल निष्पादन या संकट या इसी तरह की आकस्मिकताओं में हस्तक्षेप किया था।

8. जब धारा 8 और 9, आई. बी. सी. केवल 01.12.2016 के प्रभाव से लागू हुई, तो सी. आई. आर. पी. की शुरुआत करने का सवाल धारा 9 के तहत आवेदन केवल 01.12.2016 से ही संभव था। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई पार्टी, जो अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है।

' आई. बी. सी. के तहत 'परिचालन लेनदार' परिचालन ऋण होने का दावा करता है

1 (2006) 13 एससीसी 322 [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (5) के आधार पर निलंबन की अवधि के अपवर्जन के संरक्षण का दावा करने वाली कार्यवाही के कारण से तीन साल? 8.1 उस संदर्भ में एस. आई. सी. ए. के तहत केवल उपर्युक्त प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उपयुक्त है। एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) इस प्रकार थी:

" 22. (1) जहां किसी औद्योगिक कंपनी के संबंध में, धारा 16 के तहत कोई जांच लंबित है या धारा 17 के तहत निर्दिष्ट कोई योजना तैयार या विचाराधीन है या कोई स्वीकृत योजना कार्यान्वयन के अधीन है या जहां किसी औद्योगिक कंपनी से संबंधित धारा 25 के तहत कोई अपील लंबित है, तो -

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य कानून या औद्योगिक कंपनी के ज्ञापन और संघ के लेख या किसी अन्य में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

उक्त अधिनियम या अन्य कानून के तहत प्रभावी लिखत, औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह के लिए औद्योगिक कंपनी को समाप्त करने के लिए या उसके संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी [और धन की वसूली के लिए या औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी प्रतिभूति को लागू करने के लिए या औद्योगिक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी भी गारंटी के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा] बोर्ड की सहमति के अलावा आगे की कार्यवाही की जाएगी।

या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकरण।

8.2 एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (5) ने गणना करते समय 31.08.2010 से 01.12.2016 तक की अवधि को हटाने की मांग के लिए अपीलार्थी पर भरोसा किया।

सीमा की अवधि इस प्रकार थी:

" 22. कानूनी कार्यवाही, अनुबंध आदि का निलंबन -

(1)

(2)

(3)

(4)

सबरमति गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

(5) किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व के प्रवर्तन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसके दौरान यह या उसके प्रवर्तन के लिए उपाय बना रहता है।

इस धारा के तहत निलंबित को बाहर रखा जाएगा।

9. इस प्रकार, एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1), जैसा कि ऊपर निकाला गया है, यह स्पष्ट करेगी कि इसके लिए किसी भी कार्यवाही को करने के लिए एक वैधानिक प्रतिबंध था। किसी औद्योगिक कंपनी के खिलाफ उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिकार की प्राप्ति तब होती है जब एक बार धारा 16, एस. आई. सी. ए. के तहत उसके खिलाफ जांच लंबित होती है या उसकी धारा 17 के तहत निर्दिष्ट कोई योजना तैयार या विचाराधीन होती है या इसके तहत एक स्वीकृत योजना होती है।

कार्यान्वयन या जहां धारा 25 के तहत एक अपील

औद्योगिक कंपनी लंबित है, सिवाय बोर्ड या अपीलीय प्राधिकरण की सहमति के, जैसा भी मामला हो। जैसा कि पहले देखा गया है, एस. आई. सी. ए. को निरस्त कर दिया गया और आई. बी. सी. (धारा 7 से 9 और कई अन्य धाराएं) उसी दिन यानी 01.12.2016 पर लागू हो गई।

10. धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदकों को दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय 31.08.2010 से 01.12.2016 तक की अवधि को हटाने के अपने दावे का समर्थन करने के लिए अपीलार्थी द्वारा, विशेष रूप से पैराग्राफ 43 (vii) में इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया जाता है। जहाँ तक प्रासंगिक है, यह इस प्रकार है: -

" 43. पूर्वगामी चर्चाओं के लिए हम आयोजित करते हैं:

(i)

(v)

(vi)

.....

(vii) यह एक सुस्थापित नियम है कि किसी प्रावधान का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए जो उसके उद्देश्य को प्रभावी बनाए। और उस शरारत को ठीक करने के लिए जिसके आलोक में इसे लागू किया गया था। धारा 22 का उद्देश्य, गारंटियों को कानूनी सुरक्षा से बचाना है।

प्रिंसिपल [2023] 4 एस. सी. आर. के बी. आई. एफ. आर. के संदर्भ में कार्यवाही लंबित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋणी, यह सुनिश्चित करना है कि पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं होगी के विरुद्ध अपनाई गई पृथक् कार्यवाही द्वारा पराजित किया जाए एक बीमार कंपनी के गारंटर। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यह है यह अनिवार्य है कि धारा 22 में "वाद" अभिव्यक्ति दी जाए। इसके स्पष्ट अर्थ, अर्थात्, के लिए अपनाई गई कोई भी कार्यवाही कानून द्वारा किसी पक्ष में निहित अधिकार की प्राप्ति। यह होगा स्पष्ट रूप से मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है। "

(जोर दिया

गया)

11. इस प्रकार तय की गई स्थिति के आलोक में, अमरजीत सिंह में

पाथेजा का मामला (ऊपर), पहले के दो-कैलाश नाथ अग्रवाल और अन्य मामलों में इस अदालत के न्यायाधीश पीठ के फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक है। वी. यह भी एक मामला था, जिसमें इस सवाल पर विचार किया गया था कि क्या धारा 22, एस. आई. सी. ए., बीमार कंपनी के गारंटर्स को सुरक्षा प्रदान करती है या केवल बीमार कंपनी को। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि कैलाश नाथ अग्रवाल के मामले (उपरोक्त) में निर्णय नहीं था।

परमजीत सिंह पाथेजा के मामले (ऊपर) का फैसला करते हुए बाद की पीठ के ध्यान में लाया गया। दूसरे शब्दों में, बाद वाले मामले का फैसला प्रति इनक्यूरेयम किया गया था। कैलाश नाथ अग्रवाल के मामले में, विचार करने के बाद

इस अदालत ने कहा कि "कार्यवाही" और फिर "वाद" शब्दों को अलग-अलग अर्थ रखने के रूप में अलग-अलग समझा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अलग-अलग चीजों को दर्शाने के लिए उठाया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) केवल औद्योगिक कंपनी के खिलाफ वसूली को प्रतिबंधित करती है और वसूली के खिलाफ गारंटर्स को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी।

कार्यवाही।

12. उपरोक्त परस्पर विरोधी निर्णयों से हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है।

केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इस अदालत के बाद के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में इस मुद्दे पर आगे विचार करना। बनाम एम/एस। अरिहंत श्रेड्स लिमिटेड 3. तीन-न्यायाधीशों की पीठ, कैलाश नाथ में दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उठाए गए तर्कों और निष्कर्षों पर ध्यान देने के बाद

अग्रवाल के मामले (ऊपर) में पाया गया कि यह एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) के तहत संबंधित औद्योगिक कंपनी को दिए गए संरक्षण के दायरे के बारे में सवाल से नहीं निपटता है। इस प्रकार देखने के बाद, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त प्रश्न पर विचार किया। इस संबंध में, पैराग्राफ 32,33 और 53 प्रासंगिक हैं और इस प्रकार हैं:

2 (2003) 4 एससीसी 305

3 (2015) 1 एस. सी. सी. 166 ए. बी. ए. आर. एम. ए. टी. आई. गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

" 32. जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 22 की उप-धारा (1) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग में, यह प्रावधान है कि औद्योगिक कंपनी को बंद करने के लिए या ऐसी औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, और दूसरे भाग में यह प्रावधान है कि धन की वसूली के लिए या औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रतिभूति को लागू करने के लिए या किसी भी ऋण या ऋण के संबंध में किसी भी गारंटी के लिए कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा।

औद्योगिक कंपनी को दिए गए अग्रिम, बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकरण की सहमति के अलावा, आगे बढ़ेगा या आगे बढ़ेगा।

33. निस्संदेह, वर्तमान कार्यवाहियाँ "। वसूली के लिए आवेदन को विशेष रूप से कार्यवाही के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह के लिए, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसी कार्यवाही है जिसके परिणामस्वरूप और वास्तव में कंपनी की संपत्ति के खिलाफ निष्पादन और संकट हुआ था और इसलिए इसे औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कार्यवाही के रूप में माना जा सकता है। हमारा विचार है कि ऐसा निर्माण संसद के इरादे के भीतर होगा जहां भी ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है जो ऋणकर्ता की संपत्ति के बंधक या गिरवी द्वारा सुरक्षित की गई है। निश्चित रूप से, यह समझने का कोई उद्देश्य नहीं है कि संसद का इरादा था कि संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा वसूली के लिए इस तरह के आवेदन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन केवल इसके निष्पादन में बाधा डाली जानी चाहिए या

विशेष रूप से बाधित। इस संदर्भ में, यह याद रखा जा सकता है कि वसूली के लिए एक आवेदन के माध्यम से कार्यवाही

के तहत प्रदान की गई संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार

आर. डी. डी. बी. अधिनियम का उल्लेख धारा 22 में केवल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि आर. डी. डी. बी. अधिनियम तब अधिनियमित नहीं किया गया था।

53. इसके अलावा, हमने एस. आई. सी. ए. के धारा 22 के दायरे से वसूली आवेदन को बाहर करने के इरादे में कुछ भी विपरीत नहीं पाया है, वास्तव में इस तरह के बहिष्कार का कोई कारण नहीं हो सकता है क्योंकि प्रावधान का उद्देश्य एक बीमार कंपनी की संपत्तियों की रक्षा करना है, ताकि बी. आई. एफ. आर. द्वारा इसके पुनरुद्धार के उद्देश्य से उनसे सर्वोत्तम संभव तरीके से निपटा जा सके। पंजाब राज्य में बनाम। द ओकारा ग्रेन बायर्स सिंडिकेट [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लिमिटेड मनु/एससी/0023/1963: ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 669, न्यायालय

परोपकारी को संरक्षित करने के महत्व को स्पष्ट किया

कानून का उद्देश्य और अवलोकन किया गया:

कानून, कि यह विधायिका का इरादा था कि यह बाध्य होगा ", और यह कि बाध्य करने का इरादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाएगा यदि कानून का लाभकारी उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा जब तक कि सरकार बंधी हुई "।

13. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केएसएल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या वसूली की जाएगी।

बैंकों और वित्तीय ऋणों की वसूली के तहत आवेदन

एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) में निहित बार को देखते हुए संस्थान अधिनियम, 1963 (आर. डी. डी. बी. अधिनियम) किसी बीमार कंपनी के खिलाफ होगा या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से, यह पता लगाने के बाद भी कि आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत 'वसूली के लिए आवेदन' को विशेष रूप से किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कार्यवाही के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, यह माना गया कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी कार्यवाही है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की संपत्ति के खिलाफ निष्पादन और संकट हो सकता है और इसलिए, इसे औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के खिलाफ निष्पादन, संकट या इसी तरह की कार्यवाही के रूप में माना जा सकता है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह का निर्माण संसद के इरादे के तहत होगा। इसके अलावा, इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संसद का यह अर्थ लगाने का कोई उद्देश्य नहीं होगा कि संक्षिप्त रूप से वसूली के लिए ऐसा आवेदन प्रक्रिया होनी चाहिए या आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन केवल इसके निष्पादन को बाधित या बाधित किया जाना चाहिए। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि उक्त प्रावधान का उद्देश्य बीमार कंपनी की संपत्तियों की रक्षा करना है, एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के दायरे से वसूली आवेदन को बाहर करने की मंशा के विपरीत कुछ भी नहीं पाया, ताकि इस उद्देश्य के लिए उनसे सर्वोत्तम संभव तरीके से निपटा जा सके।

बी. आई. एफ. आर. द्वारा इसका पुनरुद्धार।

14. एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) के तहत प्रावधानों और परमजीत सिंह मामले (सुप्रा) और के. एस. एल. और उद्योगों में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए

सीमित (ऊपर), यह ध्यान देने योग्य है कि हाथ में मामले में यह सबरमति गैस लिमिटेड v था।

शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

औद्योगिक कंपनी (इसमें प्रतिवादी) जिसने एस. आई. सी. ए. के प्रावधानों के तहत बी. आई. एफ. आर. से संपर्क किया और 2010 का मामला संख्या 13 दायर करके इसे 'बीमार कंपनी' घोषित कराया; कि इसके बाद अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के तहत ब्याज के साथ उपर्युक्त देय राशि की वसूली के लिए उचित अधिकार क्षेत्र के सिविल न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध करते हुए विविध आवेदन संख्या 432/2013 दायर किया;

कि उक्त आवेदन का निपटारा केवल 09.09.2015 पर किया गया था, अनुलग्नक-A40 कार्यवाही के अनुसार, वह भी केवल प्रतिवादी कंपनी को आवेदक के बकाया को इसमें शामिल करने के निर्देश के साथ। डी. आर. एस. और 2010 के अनुलग्नक-ए 40, केस No.13 और उस पर दायर एम. ए. नंबर <आई. डी. 2 के अनुसार, तब सुनवाई के लिए तैनात किया गया था। संक्षेप में, 2010 का मामला संख्या 13 बी. आई. एफ. आर. के समक्ष लंबित था जब एस. आई. सी. ए. को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.12.2016 से निरस्त कर दिया गया था और धारा 8 और 9, आई. बी. सी. ने 01.12.2016 से अपना प्रभाव लिया। इस प्रकार, जाहिर है, एस. आई. सी. ए. के तहत कार्यवाही तब बी. आई. एफ. आर. के समक्ष लंबित थी जब पक्ष से चूक हुई थी

प्रत्यर्थी कथित रूप से घटित हुआ और धारा 22 (1), एस. आई. सी. ए. और ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के आधार पर, अपीलार्थी किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही का सहारा नहीं ले सकता था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी कंपनी की संपत्तियों से वसूली हो सकती है। इन्हीं कारणों से, प्रत्यर्थी का यह तर्क भी विफल होना चाहिए कि बी. आई. एफ. आर. के समक्ष कार्यवाही लंबित होने पर अपीलार्थी मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा ले सकता था। 15. अब, हमें एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (5) के कथित इरादे पर विचार करना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इरादा ऐसे पक्ष के हितों की रक्षा करना है जिसे धारा 22 के तहत बार की परिचालन अवधि के दौरान बकाया की वसूली के अधिकार को कानूनी रूप से लागू करने से रोका गया था।

(1) , एस. आई. सी. ए., यदि यह निष्कर्ष के बाद भी अन्यथा उपलब्ध है

बी. आई. एफ. आर. के समक्ष कार्यवाही, उसमें विशेष रूप से उल्लिखित सीमा तक। हमारे अनुसार, धारा 22 (5) के तहत प्रावधानों की कोई भी अन्य समझ पूरी तरह से व्यर्थ और उद्देश्यहीन होगी। जब अपीलकर्ता इस अर्थ में बी. आई. एफ. आर. का एक पक्षकार होता है, तो हस्तक्षेप पर प्रत्यर्थी कंपनी को मसौदा पुनर्वास में अपने बकाया को शामिल करने का आदेश प्राप्त होता है। देय राशि की वसूली करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन में योजना (डी. आर. एस.) और ऐसा चरण आई. डी. 1 तक नहीं पहुंचा था, क्या यह अभिनिर्धारित करने का कोई औचित्य होगा कि एस. आई. सी. ए. के निरसन पर वह एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (5) के तहत प्रावधानों से प्राप्त लाभ का दावा नहीं कर सकता, बशर्ते कि उपर्युक्त मंच को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानूनों के तहत प्रावधान हों?

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. प्रासंगिक स्थिति में, धारा 252 का उल्लेख करना उचित है।

आई. बी. सी. का जो इस प्रकार है: -

" 252. बीमार औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान)

निरसन अधिनियम, 2003 को निर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा।
आठवीं अनुसूची में।

16.1 आठवीं अनुसूची इसकी प्रकृति और तरीके को प्रकट करेगी।

एस. आई. सी. ए. निरसन अधिनियम, 2003 की धारा 4 के उपखंड (बी) के प्रतिस्थापन के रूप में इसके तहत निर्दिष्ट संशोधन डब्ल्यू. ई. एफ.

" (ख) केंद्र द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को

सरकार इस ओर से, किसी भी अपील को प्राथमिकता देती है

अपीलीय प्राधिकरण या किया गया कोई संदर्भ या लंबित जांच

बोर्ड को या उसके समक्ष या किसी भी प्रकार की कार्यवाही

अपीलीय प्राधिकरण या बोर्ड के समक्ष लंबित

बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985

(1 1986 का) समाप्त हो जाएगा: बशर्ते कि एक कंपनी में

जिसके संबंध में ऐसी अपील या संदर्भ या जांच होती है
इस खंड के तहत निरस्त राष्ट्रीय के संदर्भ में कर सकते हैं

दिवाला और दिवालियापन के तहत कंपनी कानून न्यायाधिकरण
कोड, 2016 से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की शुरुआत

दिवाला के प्रावधानों के अनुसार और

दिवालियापन संहिता, 2016:

बशर्ते कि बनाने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा

एक कंपनी द्वारा जिसकी अपील या संदर्भ या जांच बनी हुई है
इस खंड के तहत निरस्त किया गया। .

(जोर दिया

गया)

17. प्रतिस्थापित उपखंड (ख) का अवलोकन, जैसा कि ऊपर निकाला गया है।

यह प्रकट करेगा कि किया गया संदर्भ या जांच लंबित है या कोई कार्यवाही

एस. आई. सी. ए. के अधीन बोर्ड के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी होने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। उपखंड (ख) का पहला परंतुक केवल उस कंपनी के लिए लागू समय सीमा का संदर्भ देता है जिसके संबंध में अपील या संदर्भ या पूछताछ या कोई इस प्रकार ऐसी कार्यवाही उक्त उपखंड के तहत समाप्त हो गई। उक्त परंतुक के अनुसार, ऐसी कंपनी आई. बी. सी. की शुरुआत से 180 दिनों के भीतर और सबरमति गैस लिमिटेड v के अनुसार आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. का संदर्भ दे सकती है।

शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

उसके प्रावधानों के साथ। तत्पश्चात, उक्त संशोधन था

एस. ओ. 3569 (ई) दिनांक 25.11.2016 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निरसन अधिनियम (2003 का 1) डब्ल्यू. ई. एफ. 01.12.2016 के तहत एस. आई. सी. ए. के निरसन के कारण, किसी औद्योगिक कंपनी द्वारा शुरू की गई एस. आई. सी. ए. के तहत कोई भी लंबित कार्यवाही या जांच समाप्त हो जाएगी और 180 दिनों की ऐसी अवधि का प्रिस्क्रिप्शन केवल ऐसी कंपनी पर ही लागू होगा। कथित उपखंड (ख) और परंतुकों की जांच आई. बी. सी. के तहत अपने उपलब्ध उपचार के साथ आगे बढ़ने के लिए कम किए गए संदर्भ, जांच या कार्यवाही में विरोधी पक्षों के संबंध में ऐसी किसी विशिष्ट समय सीमा के निर्देश को प्रकट या इंगित नहीं करेगी। उक्त परिस्थितियों में, यदि ऐसा कोई विरोधी पक्ष अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है

'परिचालन लेनदार', आई. बी. सी. के तहत, यह केवल यह लिया जा सकता है कि यह अवधि के संबंध में आई. बी. सी. के तहत प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए सीमा। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि जैसा कि उस कंपनी से संबंधित है जिसका संदर्भ या

जांच या किसी भी कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया, जैसा कि उल्लेख किया गया है, इसे एस. आई. सी. ए. निरसन अधिनियम की धारा 4 के प्रतिस्थापित उपखंड (बी) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में आई. बी. सी. के तहत संदर्भ देने के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह छूट अन्य पक्षों के लिए कम की गई कार्यवाही, या संबंधित संदर्भ या जांच के लिए उपलब्ध नहीं है।

18. धारा 6, आई. बी. सी. में यह प्रावधान है कि जहां कोई भी निगमित देनदार चूक करता है, वहां एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या निगमित देनदार स्वयं आई. बी. सी. के अध्याय II के तहत प्रदान किए गए तरीके से ऐसे निगमित देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू कर सकता है। धारा 8, जो अध्याय II के तहत आती है, परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि एक परिचालन लेनदार, चूक की घटना पर, परिचालन ऋण के भुगतान या प्रतिलिपि की मांग सूचना दे सकता है।

निगमित देनदार को चूक में शामिल राशि के भुगतान की मांग करने वाले चालान का ऐसे रूप और तरीके से भुगतान करना जो निर्धारित किया जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 8 (1), आई. बी. सी. में एक प्रतीत होने वाली मुद्रण त्रुटि हुई थी क्योंकि 'अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग सूचना' के बजाय इसे 'अवैतनिक परिचालन देनदार की मांग सूचना' के रूप में मुद्रित किया जाता है। जाहिर है, यह राजपत्र अधिसूचना में भी हुआ होगा क्योंकि 'देनदार' शब्द 'अवैतनिक परिचालन' शब्दों का अनुसरण कर रहा है। उसमें प्रयुक्त 'देनदार' शब्द को 'ऋण' और 'या' में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि उद्देश्य की पूर्ति की जा सके और धारा 8 (1) को इच्छित अर्थ दिया जा सके और इस दृष्टिकोण को धारा 8 की उप-धारा (2) से ही समर्थन मिलेगा। धारा 8, आई. बी. सी. की उप-धारा 2 जहाँ तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

[2023] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

“ 8. (1)

(2) निगमित देनदार दस दिनों की अवधि के भीतर

मांग सूचना या चालान की प्रति की प्राप्ति

उप-धारा (1) में उल्लिखित के ध्यान में लाएँ

परिचालन लेनदार

(क) विवाद का अस्तित्व, यदि कोई हो, या विचाराधीनता का अभिलेख

रसीद से पहले दायर किए गए मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही का

ऐसे विवाद के संबंध में ऐसी सूचना या चालान;

(ख) अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान

(रेखांकित करें)

19. इसी तरह उक्त स्थिति दिवाला के नियम 5 से भी स्पष्ट है।

और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016 (संक्षेप में 'नियम')। प्रपत्र 3 में दिए गए निर्देश के अनुसार, जिसमें 'नियमों' के तहत निगमित देनदार को एक मांग सूचना दी जानी है, उक्त सूचना संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने से दस दिन पहले निगमित देनदार को दी जानी चाहिए। इस निर्देश का केवल यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इसे संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने से कम से कम दस दिन पहले कॉर्पोरेट देनदार पर इस सरल कारण से लागू किया जाएगा कि धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदन दायर करने की सीमा की अवधि धारा 238 ए, आई. बी. सी. द्वारा नियंत्रित होती है और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि धारा 9 का आवेदन अनिवार्य रूप से फॉर्म 3 में अग्रिम मांग सूचना की सेवा के ग्यारहवें दिन दायर किया जाना चाहिए। धारा 238 ए, आई. बी. सी., सीमा की अवधि से संबंधित, डब्ल्यू. ई. एफ. 06.06.2018 लागू हो गई है और यह इस प्रकार है: -

" 238 ए. सीमा। - सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान

(36 1963 का), जहाँ तक हो सके, कार्यवाही पर लागू होगा।
या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष अपील

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण

या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो।
20. जाहिर है, धारा 238 ए, आई. बी. सी. के प्रावधान करता है

सीमा अधिनियम, 1963 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और अन्य मंचों के समक्ष कार्यवाही के संबंध में सीमा की अवधि की गणना के लिए लागू होता है। बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय में यह स्थिति स्पष्ट रूप से स्पष्ट की गई है। पराग गुप्ता और

पैराग्राफ 43 और 48 में एसोसिएट्स और वे इस प्रकार पढ़ते हैं: -

4 (2019) 11 एस. सी. सी. 633 ए. बी. ए. आर. एम. ए. टी. आई. गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

" 43. धारा 8 (2) (ए) के अध्ययन से यह देखा जाएगा कि निगमित देनदार, ऋण देने के 10 दिनों की अवधि के भीतर

मांग सूचना की प्राप्ति, के ध्यान में लाएँ

परिचालन लेनदार एक "विवाद" का अस्तित्व। हमने देखा है कि धारा 5 (6) में परिभाषित "विवाद" में कुछ मामलों से संबंधित मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है। फिर से, धारा 8 (2) (ए) के तहत, कॉर्पोरेट देनदार,

वैकल्पिक रूप से, मांग सूचना की प्राप्ति से पहले दायर किए गए मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का खुलासा करें। इसलिए यह स्पष्ट है कि कम से कम संचालन के मामले में

समय-वर्जित, यह खारिज होने के लिए उत्तरदायी होगा। यह फिर से इस तथ्य के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक है कि जब अभिव्यक्ति " देय "और" देय और देय "संहिता की धारा 3 (11) और 3 (12) में होते हैं, वे एक" डिफॉल्ट "को संदर्भित करते हैं जो गैर-देय है।

उस ऋण का भुगतान जो कानून में देय है अर्थात ऐसा ऋण देय नहीं है।

सीमा के कानून द्वारा वर्जित। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक ही शब्द एक समान संदर्भ में आता है, कानून के प्रारूपक का इरादा है कि शब्द का अर्थ एक ही है।

और संहिता के 8, यह स्पष्ट करते हुए कि एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया केवल हो सकती है उन ऋणों के संबंध में एक वित्तीय या परिचालन लेनदार द्वारा शुरू किया गया जो समय-बाधित नहीं हुए हैं।

48. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम लागू है

संहिता की शुरुआत से संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों के लिए, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आकर्षित होता है। इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि चूक आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां मामले के तथ्यों में, [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू किया जा सकता है इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी। "

(जोर दिया गया)

21. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय

(उपर्युक्त) इस प्रकार यह प्रकट करेगा कि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 और 5 आई. बी. सी. की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होते हैं। ऐसा हो, स्थिति यह है कि सीमा की अवधि उपार्जित राशि को लागू करने के अधिकार से तीन साल है, लेकिन देरी पर्याप्त आधारों पर माफ की जा सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तीसरे कॉलम में कहा गया है कि आवेदन करने का अधिकार कब प्राप्त होता है। बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम के निर्णय में। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज

प्राइवेट लिमिटेड और Anr.5 इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया 'आवेदन करने का अधिकार कब प्राप्त होगा?' उक्त निर्णय का अनुच्छेद 32, जहाँ तक इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

" 32. जब संहिता की धारा 238-ए को उपरोक्त के साथ पढ़ा जाता है।

अभिनव में इस न्यायालय के सुसंगत निर्णयों का उल्लेख किया गया

उद्योग [नवप्रवर्तनशील उद्योग लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक, (2018)

1 एस. सी. सी. 407], बी. के. शैक्षिक सेवाएँ [बी. के. शैक्षिक सेवाएँ]

सर्विसेज (पी) लिमिटेड v. पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एससीसी

633], स्विस् रिबन [स्विस् रिबन (पी) लिमिटेड v. भारत संघ,

(2019) 4 एस. सी. सी. 17], के. शशिधर [के. शशिधर बनाम। भारतीय ओवरसीज बैंक, (2019) 12 एससीसी 150], जिग्नेश शाह [जिग्नेश]

शाह बनाम। भारत संघ, (2019) 10 एस. सी. सी. 750], वाशदेव आर.

भोजवानी [वाशदेव आर. भोजवानी बनाम। अभ्युदय कृपा बैंक लिमिटेड, (2019) 9 एस. सी. सी. 158], गौरव हरगोविंदभाई दवे [गौरव

हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (भारत) लिमिटेड, (2019) 10 एस. सी. सी. 572] और सागर शर्मा [सागर शर्मा]

बी. फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड, (2019) 10 एससीसी 353] क्रमशः

निम्नलिखित मूल बातें निस्संदेह सामने आती हैं:

(क) कि संहिता एक लाभकारी विधान है जिसका उद्देश्य
निगमित देनदार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और यह केवल एक पैसा नहीं है
पुनर्प्राप्ति कानून;

(ख) कि सी. आई. आर. पी. का उद्देश्य प्रतिकूल होना नहीं है
निगमित देनदार लेकिन हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से है
निगमित देनदार;

5 (2020) 15 एस. सी. सी. 1 ए. बी. ए. आर. एम. ए. टी. आई. गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

(ग) संहिता का उद्देश्य समय की पाबंदी वाले ऋणों को नया जीवन देना नहीं है; (घ) कि संहिता की धारा 7 के तहत सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग करने वाले आवेदन के लिए सीमा की अवधि शासित है।

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा और इसलिए, उस तारीख से तीन साल है जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है;

(ई) कि एक वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए ट्रिगर कॉर्पोरेट देनदार की ओर से डिफॉल्ट है, अर्थात, कोड के तहत आवेदन करने का अधिकार उस तारीख को प्राप्त होता है जब डिफॉल्ट होता है; (च) संहिता में निर्दिष्ट व्यतिक्रम वह है जो निगमित देनदार द्वारा वास्तविक गैर-भुगतान का होता है जब कोई ऋण हो जाता है।

देय और देय; और (छ) यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई थी, तो आवेदन समय-वर्जित होगा, सिवाय उन मामलों के जहां, तथ्यों के आधार पर, दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सकता है; और

(ज) संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन बंधक दायित्व के प्रवर्तन के लिए नहीं है और अनुच्छेद 62 इस आवेदन पर सीमा अधिनियम लागू नहीं होता है।

22. पैराग्राफ 34,34,1,38,8.1 से निम्नलिखित प्रासंगिक पाठ उपरोक्त संदर्भ में ध्यान देने योग्य हैं और वे पढ़ते हैं

" 34 जैसा कि देखा गया है, बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज [बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड v. पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्स,

(2019) 11 एस. सी. सी. 633, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के लिए सीमा अवधि तीन है।

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान किए गए वर्ष, जो चूक की तारीख से शुरू होता है और केवल बढ़ाया जा सकता है

सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करके, यदि देरी को माफ करने का कोई मामला बनाया जाता है। पैरा में निष्कर्ष

12 जिग्नेश शाह बनाम जिग्नेश शाह। भारत संघ, (2019) 10 एस. सी. सी. 750] यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय ने वास्तव में बी. के. शैक्षिक सेवाओं [बी. के.] में बताए गए सिद्धांतों को लागू किया।

शैक्षिक सेवा (पी) लिमिटेड v. पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एस. सी. सी. 633], और अभिनिर्धारित किया कि समापन याचिका [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डिफॉल्ट की तारीख से तीन साल से अधिक समय तक दायर करने पर समय द्वारा रोक लगा दी गई थी।

34.1 . बाद के फैसलों में भी, इस न्यायालय ने बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज [बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड में कानून की घोषणा को लगातार लागू किया है। पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एससीसी 633]। जैसा कि देखा गया है, वाशदेव आर. भोजवानी [वाशदेव आर. भोजवानी बनाम अभ्युदय कृपा बैंक लिमिटेड, (2019) 9 एस. सी. सी. 158], इस न्यायालय ने इस उद्देश्य के लिए कार्रवाई के निरंतर कारण का सुझाव देने वाले तर्क को खारिज कर दिया

हरगोविंदभाई दवे [गौरव हरगोविंदभाई दवे बनाम परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कं. (इंडिया) लिमिटेड, (2019) 10 एस. सी. सी. 572], जहां संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन में चूक की तारीख एन. पी. ए. की तारीख यानी 21-7-2011 बताई गई थी, इस अदालत ने माना कि सीमा एन. पी. ए. की तारीख से चलने लगी और इसलिए, 3-10-2017 पर संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

38. यह प्रश्न कि क्या संहिता के प्रवर्तन की तारीख (अर्थात 1-12-2016) संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है और इसलिए,

वर्ष 2018 में किया गया विचाराधीन आवेदन, सीमा के भीतर है, अधिक समय देने के लायक भी नहीं है। विवादित आदेश के पैरा 21 पर एक नंगी नज़र [बाबूलाल वर्धा जी गुर्जर बनाम वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 295] अनुमान लगाने के लिए कुछ नहीं छोड़ता है कि

अपीलीय न्यायाधिकरण की टिप्पणियाँ केवल थीं

धारा 7 के तहत संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से ही शुरू होना है। इसी तरह, सीमा अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी चीज़ को इस प्रस्ताव का समर्थन करने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कहा गया। वास्तव में, इस तरह की टिप्पणियाँ इस न्यायालय द्वारा बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज [बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड में घोषित कानून के दायरे में थीं। पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एससीसी 633]।

सबरमति गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

38.1 . ऐसा प्रतीत होता है कि दिए गए समय पर, एन. सी. एल. ए. टी. अन्य मामलों में भी इस तरह के प्रस्ताव को आसानी से अपना रहा था, ताकि समान अनुप्रयोगों को सीमा के भीतर माना जा सके। एन. सी. एल. ए. टी. के इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा सागर शर्मा [सागर शर्मा बनाम। फीनिक्स ए. आर. सी. (पी) लिमिटेड, (2019) 10 एस. सी. सी. 353] जहाँ, बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज [बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम. पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्स, (2019) 11 एस. सी. सी. 633] यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि संहिता के लागू होने की तारीख संहिता के उद्देश्यों के लिए किसी भी सीमा अवधि को शुरू करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक थी, इस अदालत ने कहा: (सागर शर्मा मामला [सागर शर्मा बनाम। फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड, (2019) 10 एससीसी 353], एससीसी पी। 354 , पैरा 3)

" 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि हमारे निर्णयों का अक्षरशः पालन किया जाता है। आई. बी. संहिता के लागू होने की तारीख संहिता के तहत दायर आवेदनों के लिए सीमा का कारण नहीं बनती है और न ही हो सकती है। समान रूप से, चूंकि "आवेदन" वे याचिकाएं हैं जो संहिता के तहत दायर की जाती हैं, इसलिए यह सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 है जो

ऐसे आवेदनों पर लागू होगा।

23. धारा 7, आई. बी. सी. के संबंध में तय किए गए उपर्युक्त पद धारा 9, आई. बी. सी. पर लागू होंगे। संक्षेप में, जैसा कि संबंधित है

धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदन, आई. बी. सी. के लागू होने की तारीख, अर्थात् 01.12.2016 सीमा का कारण नहीं बनेगी और धारा 9, आई. बी. सी. के तहत सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन के लिए सीमा की अवधि उस तारीख से तीन साल होगी जब आवेदन करने का अधिकार सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान किया गया है और आगे

धारा 9 के तहत, आई. बी. सी. उसी के रूप में केवल अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय में प्रामाणिक रूप से कार्यवाही के समय के बहिष्करण के लिए प्रदान करता है।

24. जब धारा 9 के तहत सी. आई. आर. पी. शुरू करने की सीमा अवधि होती है, तो आई. बी. सी. की गणना डिफॉल्ट की तारीख से की जानी चाहिए, जो कि [2023] 4 एस. सी. आर. की तारीख के विपरीत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. बी. सी. की शुरुआत और उसके लिए निर्धारित अवधि, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 137 द्वारा प्रदान की गई तीन साल की अवधि है और यह डिफॉल्ट की तारीख से शुरू होगी और केवल इसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का अनुप्रयोग न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी है कि वह विलंब को माफ करने के दावे पर विचार करे जब एक बार संबंधित कार्यवाही सीमा की अवधि से परे दायर की जाती है।

25. जैसा कि सीमा अधिनियम की धारा 5 से संबंधित है, 'पर्याप्त कारण' दिखाना देरी को माफ करने का एकमात्र मानदंड है। पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हम पहले से ही एक औद्योगिक के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए कानूनी प्रतिबंध पर ध्यान दे चुके हैं। कंपनी धारा 22 (1), एस. आई. सी. ए. के आधार पर और जाहिर है, जब कोई पक्ष इस प्रकार बी. आई. एफ. आर. की अनुमति के बिना बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने से कानूनी रूप से अक्षम था और यहां तक कि

इसके लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी गई थी कि कानूनी कार्यवाही के निलंबन की अवधि एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (5) के संदर्भ में ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित है। धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदन के संबंध में ऐसी अवधि के अपवर्जन के प्रावधानों के अभाव में, धारा 238 ए, आई. बी. सी. और सीमा अधिनियम के तहत प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन के बावजूद, ऐसे पक्ष के लिए कानूनी रूप से जो उपलब्ध है, वह सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण के रूप में निर्दिष्ट करना है। ऐसे में संभाव्यता, किसी विशेष मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार, देरी की अवधि और धारा 22 (1), एस. आई. सी. ए. आदि के तहत अधिकार के निलंबन द्वारा कवर की गई अवधि, देरी की माफी के सवाल पर विचार किया जाना चाहिए ताकि इसके परिणामस्वरूप अन्याय न हो क्योंकि पक्ष को वैधानिक रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से रोका गया था।

संबंधित औद्योगिक कंपनी। एतऽ पहिने तैयार कयल गेल पहिल प्रश्नक उत्तर तदनुसार देल गेल अछि।

26. इस मामले में, निर्विवाद रूप से, इस सवाल पर विचार नहीं किया गया कि क्या धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदन दाखिल करने के मामले में देरी हुई है या नहीं। आक्षेपित आदेश के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि चूक की तारीख और धारा 9 के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख को ध्यान में रखने के बाद, आई. बी. सी. ने इसे समयबद्ध माना। जब एक बार ऐसा पाया जाता है तो हम मामले को नए सिरे से सीमा के प्रश्न पर विचार करने के लिए भेज देते, लेकिन इस तथ्य के लिए कि धारा 9 के तहत आवेदन, आई. बी. सी. को 'पहले से मौजूद विवाद' के अस्तित्व का कारण बताते हुए भी खारिज कर दिया गया था।

सबरमति गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

27. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने स्थिरता या अन्यथा पर अपनी प्रतिद्वंद्वी दलीलों के समर्थन में विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है

पक्षकारों के बीच 'पूर्व-विद्यमान विवाद (ओं)' के अस्तित्व के आधार पर कथित आवेदन को खारिज करना। फिर भी, हमारा विचार है कि इस संबंध में, केवल इन्फ्रा संदर्भित किए जाने वाले निर्णयों पर विचार करने की आवश्यकता है। विरोधाभासी रूप से, दोनों पक्षों ने मैक्केरी बैंक लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। शिल्पी केवल टेक्नोलॉजीज

सीमित "। 28. मैक्केरी बैंक लिमिटेड के मामले (ऊपर) पर अपीलार्थी द्वारा इस बात को ध्यान में रखने के लिए भरोसा किया जाता है कि प्रमाण पत्र का उत्पादन /

के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थान का विवरण धारा 9 (3) (सी), आई. बी. सी. के तहत संबंधित परिचालन लेनदार सी. आई. आर. पी. को सक्रिय करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है और इसलिए, इसका आग्रह होगा

इसके तहत निर्धारित कानून का उल्लंघन। मैक्केरी बैंक लिमिटेड (ऊपर) में, पैराग्राफ 16 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: -

" 16. जब हम धारा 9 (3) के खंड (सी) पर आते हैं, तो यह भी उतना ही स्पष्ट है कि वित्तीय संस्थान से प्रमाण पत्र की एक प्रति

पुष्टि करने वाले प्रचालन लेनदार के खातों को बनाए रखना

यह निश्चित रूप से एक पूर्व शर्त नहीं है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा एक अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया जाता है

"पुष्टि" अभिव्यक्ति यह स्पष्ट करती है कि यह केवल सबूत का एक टुकड़ा है, हालांकि सबूत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टुकड़ा है, जो केवल "पुष्टि" करता है कि कोई अवैतनिक भुगतान नहीं है

परिचालन ऋण। यह तब स्पष्ट हो जाता है जब हम धारा 9 (3) के खंड (डी) पर जाते हैं जिसके लिए ऐसी अन्य जानकारी की आवश्यकता होती है

निर्दिष्ट किया जा सकता है साथ में भी प्रस्तुत किया जाना है आवेदन "।

29. इस प्रकार यह स्थिति उचित रूप से तय की गई है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने अपने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उक्त निर्णय पर भरोसा किया कि 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के अस्तित्व को खारिज करना चाहिए।

धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदन।

30. मैक्केरी बैंक लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 13 और 14 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: -

" 13. एक संयुक्त पठन पर ध्यान देने वाली पहली बात

संहिता की धारा 8 और 9, जैसा कि मोबिलॉक्स में समझाया गया है

6 (2018) 2 एससीसी 674 [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नवाचार (पी) लिमिटेड बनाम। कीरूसा सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड (2018) 1 एससीसी

353 , अनुच्छेद 33 से 36 पर 21-9-2017 पर निर्णय लिया गया है कि धारा

9 (1) कोड को ट्रिगर करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें शामिल हैं

जहाँ तक एक परिचालन लेनदार का संबंध है। आवश्यकताएं

कोड को ट्रिगर करने के लिए आवश्यक तत्व हैं:

(i) एक डिफ़ॉल्ट की घटना;

(ii) अवैतनिक परिचालन की मांग सूचना का वितरण।

शामिल राशि के भुगतान की मांग करने वाला ऋण या चालान;

और

(iii) यह तथ्य कि परिचालन लेनदार को प्राप्त नहीं हुआ है।

निगमित देनदार से 10 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान

मांग सूचना की प्राप्ति या मांग करने वाले चालान की प्रति

भुगतान, या निगमित देनदार से जवाब प्राप्त किया जो

पूर्व-विद्यमान विवाद के अस्तित्व का संकेत नहीं देता है या पुनर्भुगतान।

अवैतनिक परिचालन ऋण का

14. इन शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन किया जाता है।

तब संहिता की धारा 9 (2) के तहत दायर किया जा सकता है

निर्धारित तरीके से, ऐसे शुल्क के साथ जो दिया गया हो

निर्धारित किया गया।

(जोर दिया गया)

31. इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निर्णय में v. आईसीआईसीआई बैंक

Anr.7, पैराग्राफ 29 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 29. धारा 7 की योजना इसके विपरीत है -

धारा 8 के तहत योजना जहां एक परिचालन लेनदार है

एक डिफ़ॉल्ट की घटना, पहले एक मांग सूचना देने के लिए

परिचालन ऋणी को भुगतान न किए गए ऋण का

संहिता की धारा 8 (1) में प्रावधान किया गया है। धारा 8 (2) के तहत,

निगमित देनदार, प्राप्ति के 10 दिनों की अवधि के भीतर कर सकता है।

में उल्लिखित मांग सूचना या चालान की प्रति

वाद या मध्यस्थता कार्यवाही, जो पूर्व-विद्यमान है अर्थात्
प्राप्त होने से पहले

निगम द्वारा ऐसी सूचना या चालान

ऋणी। जिस क्षण इस तरह के विवाद का अस्तित्व होता है,
चंगुल से बाहर निकल जाता है।

परिचालन लेनदार संहिता के

ख) 1 एस. सी. सी. 407 ए. बी. ए. आर. एम. ए. टी. आई. गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]³². ऊपर उल्लिखित निर्णयों की जांच से पता चलता है कि 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के अर्थ में धारा 9 आई. बी. सी. के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह है कि क्या प्रत्यर्थी ने एक मौजूदा विवाद के रूप में वर्णित विवाद उठाया था ताकि अपीलार्थी आर धारा 9, आईबीसी के आवेदन को खारिज किया जा सके। मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) में,

अनुच्छेद 33 और 51 में स्पष्ट रूप से, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: -

" 33.संहिता की धारा 8 और 9 के तहत योजना दिखाई देती है।

कि एक परिचालन लेनदार, जैसा कि परिभाषित किया गया है,

चूक की घटना (यानी किसी ऋण का भुगतान न करने पर, कोई भी हिस्सा जिसका देय और देय हो गया है और नहीं किया गया है)

चुकाया गया), इस तरह के अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग सूचना दें या भुगतान की मांग करने वाले चालान की प्रति दें।

निगमित ऋणी को निर्धारित प्रपत्र में ऐसी राशि

दिवाला और दिवालियापन का नियम 5

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण) नियम, 2016 जिसे प्रपत्र 3 या 4 के साथ पढ़ा जाता है,

जैसा भी मामला हो [धारा 8 (1)]। ऐसी मांग सूचना या चालान की प्रति की प्राप्ति के 10 दिनों की अवधि के भीतर, निगमित देनदार को परिचालन लेनदार के ध्यान में एक विवाद के अस्तित्व और/या विवाद का रिकॉर्ड लाना चाहिए।

के समक्ष दायर किसी वाद या मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता

ऐसे विवाद के संबंध में ऐसी सूचना या चालान की प्राप्ति

[धारा 8 (2) (ए)]। महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाद और/या वाद या मध्यस्थता कार्यवाही का अस्तित्व पहले से मौजूद होना चाहिए अर्थात् यह मांग सूचना या चालान की प्राप्ति से पहले मौजूद होना चाहिए, जैसा भी मामला हो। [.....] यह केवल तभी होता है जब उक्त 10 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, परिचालन लेनदार को निगम से भुगतान प्राप्त नहीं होता है। देनदार या विवाद की सूचना, कि परिचालन लेनदार धारा 9 (1) और 9 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करके दिवालिया प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। [.] यह आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है यदि विवाद का नोटिस दिया गया है।

प्रचालन लेनदार द्वारा प्राप्त किया गया है या सूचना उपयोगिता [धारा 9 (5) (ii) (d)] में विवाद का रिकॉर्ड है। धारा 9 (5) (ii) (d) किसी मौजूदा विवाद की सूचना को संदर्भित करती है जो इस प्रकार प्राप्त हुई है, क्योंकि इसे धारा के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

8 (2) (ए)। इसके अलावा, यदि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है

कोई भी प्रस्तावित समाधान पेशेवर, आवेदन कर सकता है
अस्वीकार किया जाए [धारा 9 (5) (ii) (e)]।

23] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

51. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार परिचालन लेनदार

एक आवेदन दायर किया है, जो अन्यथा पूरा है,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए

प्रचालन लेनदार या विवाद का कोई अभिलेख है सूचना उपयोगिता। यह स्पष्ट है कि इस तरह की सूचना को लाना चाहिए

विवाद या तथ्य कि कोई मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही पक्षकारों के बीच किसी विवाद से संबंधित मामला लंबित है। इसलिए,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इस स्तर पर जो कुछ भी देखना है वह है

क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की आवश्यकता है जांच और यह कि "विवाद" स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं है

सबूत। भूसी से अनाज को अलग करना महत्वपूर्ण है। और एक नकली बचाव को अस्वीकार करना जो केवल दिखावा है।

हालाँकि, ऐसा करने में, न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है

कि रक्षा के सफल होने की संभावना है। अदालत ने नहीं किया

इस चरण में विवाद के गुण-दोष की जांच की जाती है सिवाय इसके कि किस हद तक

ऊपर बताया गया है। जब तक वास्तव में कोई विवाद मौजूद है और मिथ्या, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण को आवेदन को अस्वीकार करना होगा।

(जोर दिया

गया)

33. इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार तय की गई स्थिति के आलोक में

मैक्वेरी बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) और मोबिलॉक्स इनोवेशन (पी) लिमिटेड।

(ऊपर), हम इस प्रश्न की जांच करेंगे कि क्या पक्षकारों के बीच कोई 'पूर्व-विद्यमान विवाद' था, जो अपीलार्थी द्वारा दायर सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन को खारिज करने की गारंटी देता है।

34. इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अनुलग्नक ए-41

धारा 8, आई. बी. सी. के तहत मांग नोटिस अपीलार्थी द्वारा 01.04.2017 पर जारी किया गया था और प्रतिवादी ने पत्र अनुलग्नक के अनुसार उसी का जवाब दिया था। ए-42 दिनांकित 10.04.2017 पत्र। , अनुलग्नक ए-41 की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर। जाहिर है, प्रत्यर्थी ने अनुलग्नक ए-42 के जवाब में यह तर्क दिया कि गैस आपूर्ति में कमी आई है और गैस आपूर्ति के विच्छेद के कारण उसे भारी नुकसान हुआ है। यह सच है कि मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में जिस पर विचार किया जाना है, वह है किसी विवाद का अस्तित्व या अन्यथा और/या मांग सूचना या SABARMATI GAS LIMITED v की प्राप्ति से पहले मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही।

शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

चालान, जैसा भी मामला हो। हाथ में मामले में, जैसा कि पहले देखा गया था, अपीलार्थी ने 01.04.2017 पर 2016 के नियम 5 के साथ पठित धारा 8, IBC के तहत एक मांग नोटिस जारी किया था। जाहिर है, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने दिनांकित एक पत्र (अनुलग्नक ए-36) का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से मौजूद विवाद का अस्तित्व उसी से प्रकट हुआ है। अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 03.01.2013 के पत्र के उत्तर के रूप में प्रत्यर्थी द्वारा जारी किया गया उक्त पत्र इस प्रकार है:

" तारीख: 04.01.2013

को,

निदेशक,

साबरमती गैस लिमिटेड,

गांधीनगर।

आदरणीय साहब,

संदर्भ: आपका दिनांकित पत्र 03.01.2013

हम एस. आई. सी. ए. की धारा 22 के अनुसार मामला संख्या 13/2010 के माध्यम से बी. आई. एफ. आर. के साथ पंजीकृत हैं, कोई दंडात्मक वसूली नहीं की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि हमारे घरों में गैस की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है। उत्पादन के कारण इकाई को भारी नुकसान हो रहा है। रेलवे बोर्ड और रेलवे बोर्ड सहित विभिन्न पक्षों को सामग्री की आपूर्ति न करने के कारण नुकसान और अधिक बढ़ा-चढ़ाकर हो रहा है।

अन्य बड़ी इकाइयाँ।

कृपया ध्यान दें कि आप प्रत्यक्ष नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं।

अनुबंध (या आपूर्ति जिसके लिए आपको केवल जिम्मेदार ठहराया जाएगा) के गैर-अनुपालन के लिए दंड सहित।

को ध्यान में रखते हुए हम बिलों के भुगतान के लिए सहमत हैं

उपरोक्त विषय

और आपसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध करते हैं (या पुराने बिलों के भुगतान तक)

पुनर्गठन पर माननीय बी. आई. एफ. आर. द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

आपके सर्वोत्तम सहयोग की उम्मीद है।

आभार व्यक्त करते हुए,

शाह अलॉयज लिमिटेड के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता "[2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि उक्त पत्र दिनांक 04.01.2013 के अंतिम पैरा से इस तथ्य का पता चलेगा कि प्रत्यर्थी भुगतान या बिलों को लागू करने के लिए सहमत हुआ था और

केवल पुराने बिलों के भुगतान की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है जब तक कि बी. आई. एफ. आर. द्वारा पुनर्गठन पर सहमति नहीं बन जाती है और दूसरे शब्दों में, विवाद का अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा, अपीलार्थी ने अनुलग्नक 40 के पैराग्राफ 2.7 और 2.10 (iv) पर बहुत अधिक भरोसा किया, जो कि 2010 के मामले में बी. आई. एफ. आर. की कार्यवाही है, ताकि इस स्थिति का प्रचार किया जा सके कि प्रत्यर्थी का देय देय राशि के संबंध में पहले से मौजूद विवाद के अस्तित्व के बारे में तर्क किसी भी आधार से रहित है। अनुलग्नक ए-40 में उपरोक्त प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं: -

“ 2.7 इसके बाद पीठ ने एम. ए. सं. 432/2013 लिया। आवेदक (साबरमती गैस लिमिटेड) का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे वकील ने सुनवाई की अगली तारीख में तैयार होकर पेश होने के लिए समय मांगा, क्योंकि वे हाल ही में इस मामले में लगे हुए हैं। कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले एल. डी. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक असुरक्षित लेनदार है और उसने आवेदक का बकाया स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि असुरक्षित लेनदार के रूप में डी. आर. एस. में उनके मिलान किए गए बकाया का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा।

डी. आर. एस. की शर्तें, जब और जब इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

2.10 सुनवाई के दौरान की गई दलीलों और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद पीठ ने निम्नलिखित आदेश जारी किए: दिशा निर्देश:

(iv) साबरमती गैस लिमिटेड द्वारा दायर एमए 432 का निपटान कंपनी को बकाया राशि को शामिल करने के निर्देश के साथ किया जाता है।

डीआरएस में आवेदक।

36. यह सच है कि अनुलग्नक 40 के अनुच्छेद 2.7 में बी. आई. एफ. आर. के समक्ष प्रत्यर्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ऐसे सभी पहलुओं का हवाला देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के संबंध में प्रतिवादी का तर्क केवल एक स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क/तथ्य का दावा है जो साक्ष्य द्वारा असमर्थित है और इसलिए, इसे न्यायाधिकरणों द्वारा खारिज कर दिया जाना था। आवेदक द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि पैराग्राफ 2.10 (iv) के निर्देश भी इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि विविध। SABARMATI GASS LIMITED v द्वारा दायर 2013 का आवेदन No.432।

शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

इसमें अपीलार्थी को प्रतिवादी कंपनी को अपीलार्थी/आवेदक की स्थिति को इसमें शामिल करने के निर्देश के साथ निपटाया गया था।

डीआरएस में।

37. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेगा कि अनुच्छेद 2.7 की जांच से ही पता चलेगा कि बी. आई. एफ. आर. के समक्ष प्रत्यर्थी की ओर से पेश होने वाले वकील द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, वह अपीलार्थी द्वारा दावा की गई राशि का पूरा भुगतान नहीं था और जो आश्वासन दिया गया था वह यह था कि अपीलार्थी के प्रति मिलान किए गए बकाया का डी. आर. एस. में असुरक्षित लेनदार के रूप में ध्यान रखा जाएगा और इसका भुगतान डी. आर. एस. की शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जब भी इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

38. इस संदर्भ में "सुलह" शब्द के अर्थ पर गौर किया जाना चाहिए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 10 वें संस्करण के अनुसार, उपयुक्त लेखांकन के संबंध में स्थिति के लिए उपयुक्त अर्थ इस प्रकार है: राशियों का समायोजन ताकि वे सहमत हों, विशेष रूप से अनुमति देकर

उत्कृष्ट वस्तुएँ "। यह विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

दिनांकित 04.01.2013 (अनुलग्नक 36) पत्र में प्रतिवादी पक्षों के बीच पहले से मौजूद विवाद के अस्तित्व को प्रकट करेगा। प्रासंगिक स्थिति में केवल मोबिलॉक्स इनोवेशन (पी) लिमिटेड (ऊपर) में दिए गए अवलोकन को याद दिलाना उचित है कि भूसी से अनाज को अलग करने का कार्य करते समय न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव पक्ष के सफल होने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि पक्षों के बीच एक विवाद मौजूद है और दूसरे शब्दों में, जो देखा जाना है वह यह है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद था जिसके उद्देश्य के लिए जांच की आवश्यकता थी न्यायनिर्णयन। अपीलार्थी द्वारा किए गए दावे के संबंध में प्रतिवादी के विवाद की प्रकृति पर ध्यान देते हुए, हम न्यायाधिकरणों के समवर्ती निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि धारा 8, आई. बी. सी. के तहत मांग सूचना की प्राप्ति से पहले पक्षों के बीच 'पूर्व-मौजूदा विवाद' मौजूद था। दूसरे शब्दों में, 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के आधार पर धारा 9, आई. बी. सी. के तहत आवेदन को खारिज करना स्पष्ट रूप से अवैध या विकृत नहीं माना जा सकता है। हमें तथ्यों और परिस्थितियों में यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि प्रतिवादी द्वारा स्थापित मामला एक स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क था। किसी भी तरह से, हम प्रत्यर्थी के मामले को नकली बताते हुए दरकिनार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम यहाँ जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि हम [2023] 4 एस. सी. आर. नहीं होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझा गया है कि प्रतिवादी द्वारा निर्धारित विवाद के संबंध में

प्रत्यर्थी 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के रूप में वर्णित विवाद को उठाने में सफल रहा है। मामले के उस दृष्टिकोण में एक बार जब हम पाते हैं कि न्यायाधिकरणों ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि पक्षों के बीच एक 'पूर्व-विद्यमान विवाद' मौजूद है, तो आई. बी. सी. के तहत धारा 9 आवेदन पर पुनर्विचार के लिए न्यायाधिकरण को मामले के रिमांड का आदेश नहीं दिया जा सकता है। 39. प्रासंगिक स्थिति में,

इस तथ्य का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, जिस पर एन. सी. एल. टी. द्वारा उचित रूप से ध्यान दिया गया है, कि प्रतिवादी ने 2017 का वाणिज्यिक मुकदमा 28.04.2017 पर दायर किया था।

अहमदाबाद में वाणिज्यिक न्यायालय ने गैस आपूर्ति बंद करने के कारण हुए नुकसान के लिए हर्जाने का दावा किया। यह सच है कि 12.07.2018 पर, उक्त वाणिज्यिक दीवानी मुकदमे को अहमदाबाद के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा सीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अनुलग्नक-बी से पता चलेगा कि उक्त मुकदमे में खारिज करने के फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी ने अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की पहली अपील संख्या 3841 दायर की थी। इसे 11.08.2021 पर निपटाया गया था, इस संयुक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से विवाद को निपटाने की अनुमति दी जाए। इस संदर्भ में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता की अधिसूचना दिनांक 29.11.2019 अपीलार्थी द्वारा ही जारी की गई है। निवेदन दर्ज करते हुए, पक्षकारों को मध्यस्थता प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए छोड़ते हुए अपील को वापस लेने की अनुमति दी गई। यह तथ्य विवादित नहीं है और वास्तव में, यह विविध मामलों में गुजरात उच्च न्यायालय के अनुलग्नक-बी, दिनांक 11.08.2021 के फैसले को देखते हुए निर्विवाद है। 2018 की पहली अपील No.3841। अनुलग्नक-बी में इसे इस प्रकार दर्ज किया गया है:

" दोनों विद्वान वकीलों ने निर्देश लिए हैं और संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा करने दें, जहां इस न्यायालय के विद्वान पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे. सी. उपाध्याय (सेवानिवृत्त) पहले ही कर चुके हैं।

29.11.2019 पर मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया और तब से

तब मामला यहाँ लंबित है।

इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि गैस आपूर्ति समझौता (जी. ए. एस.) जो अपीलार्थी और अपीलार्थी के बीच किया गया एक समझौता है।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के संबंध में प्रतिवादी दिनांक 30.05.2008 में एक मध्यस्थता खंड है अर्थात् , खंड No.17।

जब समझौता सबरमति गैस लिमिटेड v. शाह एलॉयस लिमिटेड [सी. टी. रविकुमार, जे.]

लंबित रहने तक, हमारा विचार है कि इस निर्णय में चर्चा किए गए और तय किए गए कानूनी प्रश्नों को छोड़कर, पक्षकारों को मध्यस्थ के समक्ष सभी दलीलों को उठाने की स्वतंत्रता दी जाएगी। 40.
उपरोक्त के अधीन, यह अपील खारिज हो जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान (सहायक: जहानवी तनेजा और महेन्द्र यादव, एलसीआरएस)